दैनिक जागरण

डूबने के डर से तैरना नहीं सीखा जा सकता

सस्ती राजनीति

राजस्थान के अलवर जिले में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर हो रही राजनीति बिल्कुल भी ठीक नहीं। यह शर्मनाक वारदात राजनीतिक या चुनावी लाभ लेने का विषय नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाने का है ताकि भविष्य में सभ्य समाज को विचलित करने वाली ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। इससे बुरी बात और कोई नहीं कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने इस घटना को इसलिए दबाने की कोशिश की ताकि उसका चुनाव पर कोई असर न पड़े। क्षोभ की बात केवल यही नहीं कि एफआइआर दर्ज करने में देर की गई, बल्कि यह भी है कि अपराधियों की गिरफ्तारी में भी हीला-हवाली की गई। इस पर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि लापरवाही और संवेदनहीनता का परिचय देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि यही अधिक जान पड़ता है कि आक्रोश को शांत करने के इरादे से यह कार्रवाई की गई। इस मामले में तो ऐसी कार्रवाई की जरूरत थी जिससे कोई मिसाल कायम होती। यह पुलिस के टालमटोल वाले रवैये का ही दुष्परिणाम रहा कि एक दलित महिला का उसके पति के सामने दुष्कर्म करने वालों ने अपने वहशी कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस चाहती तो इस दुष्कृत्य को रोक सकती थी, लेकिन वह चुनाव की चिंता करती रही। इतना ही नहीं, घटना का वीडियो वायरल होने पर उसने यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली कि एक और धारा जोड़ देंगे। यह नाकारापन की हद है कि घटना के करीब एक सप्ताह बाद तीन आरोपितों की गिरफ्तारी हो सकी।

अलवर कांड का खौफनाक सच सामने आने के बाद राजनीतिक दलों से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सक्रियता समझ में आती है, लेकिन इस घटना पर सस्ती राजनीति शुरू हो जाना समझ से परे है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस तरह की राजनीति इसीलिए हो रही है, क्योंकि देश में आम चुनाव हैं और दलितों के प्रति होने वाली घटनाओं को राजनीतिक मसला बनाने का चलन बन गया है। इस घटना की निंदा करने और इसे लेकर विरोधी राजनीतिक दलों पर निशाना साधने में अंतर है। इससे से बचा जाना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खुद प्रधानमंत्री भी इस मामले का जिक्र करके विरोधी दलों पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। उन्होंने मायावती को चुनौती दी कि वह राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेकर दिखाएं। इसके जवाब में बसपा प्रमुख ने प्रधानमंत्री को गुजरात की दलित विरोधी घटनाओं की याद दिलाई। यह सब न होता तो बेहतर होता। मुश्किल यह है कि राजनीतिक दल जघन्य घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की हरसंभव कोशिश करते हैं। यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर पीड़ित दलित समाज से होता है तो एक अलग तरह की राजनीति चालू हो जाती है। यह राजनीति भी अपनी-अपनी सुविधा से होती है। घटना विरोधी दल शासित राज्य में हो तो बाकी राजनीतिक दलों में खुद को दलित हितैषी दिखाने की होड़ लग जाती है। स्त्री के सम्मान को किसी जाति-समुदाय से जोड़कर न देखा जाए तो बेहतर। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि दुष्कर्म के आरोपितों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिले। यह खेदजनक है कि ऐसा नहीं हो रहा है।

आयोग की नाकामी

पश्चिम बंगाल में अब तक लोकसभा चुनाव का एक भी चरण शांतिपूर्ण व निर्बाध संपन्न नहीं हो सका। रविवार को छठे चरण के लिए वोट डाले गए, लेकिन चुनाव आयोग का तमाम सुरक्षा इंतजाम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ। विशेष चुनाव पर्यवेक्षक से लेकर विशेष पुलिस पर्यवेक्षक तक की तैनाती हुई। सामान्य पर्यवेक्षक से लेकर सूक्ष्म पर्यवेक्षक, सेक्टर आफिसर, क्विक रिस्पांस टीम तक तैनात रही। परंतु, देखा गया कि वोटरों की तो बात दीगर, यहां तक कि प्रत्याशियों तक को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जाने से रोका ही नहीं गया, बल्कि उन पर पथराव के साथ-साथ धक्का-मुक्की तक की गई। उम्मीदवारों व मीडिया कर्मियों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बल जब मौके पर पहुंचे तो उनपर भी पथराव किया गया। वहीं सत्तारूढ़ दल तृणमूल के अन्य क्षेत्र के कद्दावर नेता चुनाव वाले इलाके पुरुलिया में बिना किसी रोक-टोक के घुमते देखे गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग कितना लाचार व मजबूर दिखाई दे रहा है। मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले भाजपा के एक और तृणमूल के एक स्थानीय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। वहीं कुछ लोग गोली से जख्मी होकर पश्चिम मेदिनीपुर जिले से लेकर कोलकाता तक के अस्पताल में भर्ती हैं। पहले चरण के बाद आयोग ने कहा था कि दूसरे चरण में और पुख्ता इंतजाम होगा। इसके बाद भी कोई चरण ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हिंसा न हुई हो। वाममोर्चा के जमाने से ही हिंसा के लिए कुख्यात रहे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर इलाके में वही वाममोर्चा के जमाने जैसी हिंसा फिर दिखाई दी। क्षेत्र के प्रत्याशी को डरकर मंदिर में शरण लेनी पड़ी। उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गईं। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी भारती घोष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने गोली चला दी जिसमें एक तृणमूल समर्थक जख्मी हो गया है। वहीं कभी भाजपा समर्थकों तो कहीं माकपा समर्थकों व नेता के घर को निशाना बनाया गया तो कुछ जगह पर तृणमूल समर्थकों की भी पिटाई हुई। चुनाव आयोग का यह बंदोबस्त आखिर किस काम आया? क्या लोग निर्बाध रूप से मतदान कर पाए जिसका आयोग ने दावा किया था।

टला नहीं आइएस के आतंक का खतरा

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

दुनिया भविष्य में और आतंकी हमलों के लिए तैयार रहे, क्योंकि वजूद बचाने और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आइएस किसी भी हद तक जा सकता है

पिछले महीने श्रीलंका आतंकी हमलों से दहल गया। राजधानी कोलंबो में 21 अप्रैल को चर्चों और होटलों को निशाना बनाकर किए गए इस आतंकी हमले में 290 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। वर्ष 2009 में गृहयुद्ध की समाप्ति के दस साल बाद हिंद महासागर के इस द्वीप में हिंसा ने फिर से दस्तक दी जिसका दायरा अब फैलने की आशंका बढ़ गई है। आइएसआइएस ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी और अब उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने जम्मू-कश्मीर में भी अपना अड्डा बना लिया है। इससे पहले ऐसी खबरें भी आई थीं कि उसने बंगाल के लिए अपना 'अमीर' यानी प्रमुख नियुक्त कर दिया है। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आइएस भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन श्रीलंका आतंकी हमले से जाहिर है कि वह खत्म नहीं हुआ है। हमले के बाद आइएस ने आठ लोगों का वीडियो भी जारी किया जिन्होंने इस्लामिक स्टेट के स्वयंभू खलीफा और आतंकी संगठन आइएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। फिर अल बगदादी का दुष्प्रचार वीडियो भी जारी हुआ। पांच साल के बाद पहली बार उसका ऐसा वीडियो देखा गया। यह इस बात को दर्शाता है कि इराक और सीरिया जैसे तथाकथित गढ़ों में आइएस का सफाया होने के बावजूद उसका मुखिया न केवल जीवित है, बल्कि उसकी हालत भी ठीक-ठाक ही दिख रही है। अल फुरकान मीडिया द्वारा पोस्ट किए गए 18 मिनट के वीडियो में अल बगदादी ने श्रीलंका में बम धमाकों को अंजाम देने वालों की तारीफें कीं। उसने सीरिया के बागोज में हालिया लड़ाई का भी जिक्र किया जिसमें आइएसआइएस का आखिरी किला भी ढह गया, लेकिन उसने एलान किया कि इस्लाम की यह लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले भी उसने कहा था कि आप दुनिया को हिलाकर ही अपनी अलग दुनिया बना सकते हैं। एक वक्त इस्लामिक स्टेट इसे संभव करता भी दिख रहा था जब वह ब्रिटेन के बराबर भूभाग पर काबिज होकर करीब एक करोड़ की आबादी का भाग्यविधाता बन बैठा था। बीते कुछ वर्षों में आइएसआइएस को भारी नुकसान उठना पड़ा है जहां अमेरिका और रूस समर्थित बलों ने कई इलाकों से उसे खदेड़कर उन इलाकों से उसका कब्जा छुड़ाया जहां कभी उसकी तूती बोलती थी। आइएसआइएस आज उस आतंकी संगठन की महज छायामात्र बनकर रह गया जो कभी बहुत मजबूत हुआ करता था। मगर यह अभी भी एक एक बड़ी ताकत के रूप में कायम है जो दुनियाभर में आतंकी हमलों के लिए उकसाने का माद्दा रखता है। श्रीलंका में हुए धमाकों से इसकी पुष्टि भी होती है। अल बगदादी का वीडियो यही रेखांकित करता है कि यह संगठन भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उसे खारिज करने की भूल न करें।

आइएसआइएस की वैचारिकी सलाफी, सलाफी जिहाद और वहाबी विचारधारा से प्रेरित है। इस्लाम की ये सभी धाराएं बहुत कट्टर मानी जाती हैं जिनके अनुसार सभी गैर-मुस्लिम अल्लाह को नहीं मानते लिहाजा उन्हें मार दिया जाना चाहिए। आइएसआइएस के लक्ष्यों में शुरुआती इस्लाम के खलीफा वाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना भी शामिल है। उसके विचारों में हिंसा की भरमार है। उसके हिसाब से अगर इस्लाम को कोई दूषित करने की कोशिश करे तो इसका प्रतिकार करना होगा। हजरत मोहम्मद और उनके शुरुआती शागिर्दों ने जो नियम-कानून बनाए, उनका सख्ती से पालन अनिवार्य है। उसकी सोच में महिलाएं कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं हो सकतीं और उन्हें जिहादियों की अच्छी पत्नी बनकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। वे अच्छी मां बनकर दिखाएं और नर्स और सिलाई जैसे कामों तक सीमित रहें। नास्तिक महिलाओं को यौन दासी बनाकर उनका सामान्य वस्तुओं की भांति व्यापार किया जाए। आइएस पूरी तरह से इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों से संचालित होता है और उसके प्रवक्ता अक्सर उनका हवाला भी देते हैं।

आइएसआइएस बड़े स्तर पर पत्रिकाएं प्रकाशित कराता है, वीडियो और ऑडियो टेप बनवाता है। विभिन्न भाषाओं में उसके लिए यह सामग्री अल-हयात मीडिया सेंटर द्वारा तैयार की जाती है। अंग्रेजी में वह दबिक और रुमैया, रूसी में इस्तोक, फ्रेंच में दार-अल-इस्लाम और तुर्की में कोंस्तातिनिये जैसे प्रकाशनों से जुड़ा है। साथ ही अंग्रेजी में 'हाउ टू सर्वाइव इन द वेस्टः ए मुजाहिद्स गाइड' जैसे प्रकाशन भी कराता है। वह लगातार दुष्प्रचार सामग्री को उन इलाकों में भी फैला रहा है जहां भले ही उसकी पैठ हो या नहीं। क्या उसके लिए जमीनी आधार जरूरी है, इस सवाल का आइएस ने अपने एक प्रकाशन में इस तरह जवाब दिया है, 'क्या पश्चिम को जीत हासिल हो गई या फिर हम अपनी हार मान लेंगे। भले ही मोसुल, रक्का और अन्य शहर हमारे हाथ से निकल गए हों, लेकिन क्या हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी? कभी नहीं। असली हार तभी होगी जब हम लड़ने का जज्बा खो बैठेंगे। हम लड़ाई के आदेश का पालन कर रहे हैं और अल्लाह के बेहद करीब हैं। अपने धर्म के लिए जीना और उसी के लिए मरना ही हमारे लिए असली जीत है।'

यहां तक कि उसके ये प्रकाशन आतंकी रणनीतियों की व्याख्या करते हुए उसके सुबूत छोड़ने की अहमियत भी बताते हैं जिसका मकसद इस आतंकी संगठन का महिमामंडन और लोगों को खौफजदा करना है। रुमैया के अक्टूबर, 2016 के अंक में इसका उल्लेख है, 'किसी देश को डराने और तमाम काफिरों को मौत के घाट उतारने के लिए जरूरी नहीं कि कोई सैन्य विशेषज्ञ हो या मार्शल आर्ट का जानकार। इसके लिए बंदूक या राइफल भी जरूरी नहीं। आतंकी अभियान का यही मकसद होता है कि अल्लाह के दुश्मनों को सबक सिखाया जाए।'

भयावह क्रूरता, लोगों के सिर कलम करना, कैद में लोगों को आग में जलाकर मार देने जैसे नृशंस कृत्यों के वीडियो और फोटोग्राफ भी एक सोची-समझी रणनीति के तहत ही जारी किए जाते हैं। इसका अपने और विरोधी दोनों खेमों में असर देखा जाता है। आइएसआइएस कयामत की पुरानी परंपरा और भविष्यसूचक अनुमान पर विश्वास करता है। दुनिया को भविष्य में और आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आइएसआइएस अपने पास मौजूद किसी भी विकल्प को आजमाने की हद तक जा सकता है। अपने वजूद को बचाने के साथ ही उसे यह भी संदेश देना होगा कि अपनी जमीन गंवाने के बावजूद उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई है। यहां बड़ा सवाल यही है कि लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा की चपेट में आने से कैसे रोका जाए। वैचारिक ब्रेनवॉश के बाद वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यह उतना आसान नहीं, क्योंकि आइएसआइएस इस्लामिक धर्मग्रंथों को ही अपनी ढाल बनाता है। दूसरे धर्मों के उलट इस्लामिक धर्मग्रंथों को पूर्ण माना जाता है जिससे उनमें सुधार या संशोधनों की गुंजाइश नहीं बचती। ऐसे में केवल मुस्लिम उलेमा ही आइएसआइएस की अवधारणा का जवाब तलाश सकते हैं। इस आतंकी संगठन की महज आलोचना करने के बजाय उलेमाओं को चाहिए कि वे इसका तोड़ निकालने वाला विमर्श तैयार करें। अन्यथा आतंकी हमलों पर विराम नहीं लग पाएगा और निकट भविष्य में मानवता शांति की उम्मीद नहीं कर सकती।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

संपूर्ण समाज का संगठन है संघ

मनमोहन वैद्य

कुछ स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय हैं इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि संघ एक राजनीतिक दल है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के समय से ही स्वयं को संपूर्ण समाज का संगठन मानता और बताता रहा है। देश को मिली स्वतंत्रता के पश्चात भी संघ की इस भूमिका में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में संघ का जो संविधान बना उसमें भी यह स्पष्ट है कि यदि कोई स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय होना चाहता है तो वह अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। यह संविधान भारतीय जनसंघ की स्थापना के पहले बना है। जनसंघ की स्थापना के बाद भी उसमें अनेक स्वयंसेवक और प्रचारकों को देने के बाद भी इसमें कोई बदल नहीं हुआ है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकाधिक दल का होना स्वाभाविक ही है। संघ के संपूर्ण समाज का संगठन होने के नाते यह भी स्वाभाविक ही है कि समाज का कोई भी क्षेत्र संघ से अछूता नहीं रहेगा और स्वयंसेवक समाज एवं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय दृष्टि लेकर जाएंगे। चूंकि कुछ स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय हैं इसलिए संघ राजनीति करता है या वह राजनीतिक दल है, यह कहना अनुचित और गलत होगा। राजनीतिक दल समाज के केवल एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज का दूसरा हिस्सा भी होता है। संघ जब संपूर्ण समाज का संगठन है तो यह 'संपूर्ण' किसी एक 'हिस्से' का हिस्सा कैसे बन सकता है?

1925 में संघ की स्थापना के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते समय डॉ. हेडगेवार अन्य स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह के लिए जाने से पहले सरसंघचालक का दायित्व अपने सहकारी डॉ. परांजपे को सौंप गए थे। वह व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रह में सहभागी हुए थे और उसके लिए उन्हें एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा संघ को कांग्रेस में विलीन करने का प्रस्ताव आने पर गुरुजी ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि संघ एक दल बनने के बजाय संपूर्ण समाज का संगठन करना चाहता था। राजनीति में एक राष्ट्रीय विचार के दल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संघ को यह रिक्तता पूरी करनी चाहिए, ऐसा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्ताव आने पर गुरुजी ने कहा कि यह काम आप कीजिए। संघ आपकी सहायता करेगा, परंतु संघ संपूर्ण समाज के संगठन का अपना कार्य ही करता रहेगा।

आपातकाल के दौरान 1977 के लोकसभा चुनाव के समय जनता पार्टी की सरकार बनाने में संघ स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान था। कई दलों को लेकर बनी जनता पार्टी में अर्थात सत्ता में सहभागी होने का आकर्षक प्रस्ताव आने पर भी तत्कालीन सरसंघचालक बालासाहेब देवरस ने उसे अस्वीकार करते हुए यही कहा कि विशिष्ट परिस्थिति में संघ इस चुनाव में सहभागी हुआ था। अब संघ अपने नियत कार्य, संपूर्ण समाज के संगठन के कार्य में ही लगेगा। यह सब समझने के लिए समाज में संगठन नहीं, संपूर्ण समाज को संगठित करने के संघ के विचार के पीछे की भूमिका को समझना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2018 की प्रतिनिधि सभा में ज्येष्ठ स्वयंसेवक एमजी वैद्य आए थे। उस दिन उनका 95वां जन्मदिन था। वह बाल्यावस्था से ही संघ के स्वयंसेवक बने हुए हैं। प्रतिनिधि सभा में अपने विचार व्यक्त करते समय उन्होंने कहा, 'संघ को समझना आसान नहीं है। पश्चिम के द्वंद्वात्मक सोच से संघ को समझना संभव नहीं है। भारतीय सोच की एकात्म दृष्टि से ही आप संघ को समझ सकते हैं।'

'ईशावास्य उपनिषद' के पांचवें मंत्र में आत्म तत्व का वर्णन करते समय उपनिषदकार कहते हैं, 'तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।' अर्थात 'वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है। वह दूर है और समीप भी है। वह सब के अंतर्गत है और वही सब के बाहर भी है।' यह बात परस्पर विरोधी लगने वाली है फिर भी सत्य है। कुछ ऐसी ही बात संघ पर भी लागू होती है। संघ संपूर्ण समाज का संगठन है। समाज में विभिन्न क्षेत्र हैं। संघ इनमें से किसी एक क्षेत्र या अंग का संगठन नहीं है।

सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, राजनीति, सेवा, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में सक्रिय होते हुए भी संघ इनमें से केवल एक का संगठन नहीं है। संघ इससे ऊपर भी कुछ है। पुरुषसूक्त में कहा गया है कि 'वह पृथ्वी सहित संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर भी दस अंगुली शेष बचता है।' इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने एक समय यह कहा था कि अणु अविभाज्य है। फिर उन्होंने कहा कि अणु विभाज्य है और उसमें मुख्यतः तीन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रान। फिर कहने लगे कि तीन ही नहीं और भी अनेक सूक्ष्म कण होते हैं। फिर वे कहने लगे कि वे कण नहीं, वे तरंग के समान गुणधर्म दिखाते हैं। आगे और खोज हुई तो कहने लगे कि वे दोनों हैं, कण भी और तरंग भी। वैज्ञानिक हाइजनबर्ग ने कहा कि यह अनिश्चित ही है कि वह कण है या तरंग? यही बात 'ईशावास्य उपनिषद' भी कहता है। इसे समझेंगे तो ही भारतीय चिंतन की एकात्म दृष्टि (द्वंद्वात्मक नहीं) को आप समझ सकेंगे। तो ही संघ के असली स्वरूप को आप समझ सकेंगे। एमजी वैद्य जी ने संघ की भूमिका को इसी तरह समझाया।

संपूर्ण समाज का संगठन होने के और राजनीतिक क्षेत्र समाज का एक अंग होने के नाते इस क्षेत्र में भी संघ स्वयंसेवक सक्रिय होंगे। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होने के कारण इसमें अधिकाधिक मतदान हो, वह स्थानीय मुद्दे या छोटे विषयों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर हो और समुचित विचार कर राष्ट्र के हित में लोग मतदान करें, ऐसा जनजागरण भी स्वयंसेवक एक जागृत नागरिक होने के नाते करते हैं।

संघ का संविधान किसी भी स्वयंसेवक को (संघ के पदाधिकारी नहीं) किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का प्रचार करने से रोकता नहीं है, परंतु 90 प्रतिशत स्वयंसेवक किसी दल या उम्मीदवार के नाम का पर्चा न लेकर राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में ही जागरण करते दिखेंगे। ऐसा होते हुए भी संघ एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनता है। वह संपूर्ण समाज का संगठन ही है। यही है भारत की सर्वसमावेशी, एकात्म, सर्वांगीण विचार का मार्ग। संघ को सही अर्थों में समझने के लिए इस दर्शन को समझना आवश्यक है।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं)

response@jagran.com

सहिष्णुता

शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए सहनशीलता बेहद जरूरी है। इस क्षमता का विकास करके हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सहिष्णुता ही वह विशेषता है जो नफरत, द्वेष एवं तनाव की संस्कृति को शांति एवं सौहार्द की संस्कृति से प्रतिस्थापित करती है। सहिष्णुता कोई एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो मानव एवं मूलभूत मूल्यों में आस्था से निर्देशित होता है। इसके अभ्यास से आप क्रिया-प्रतिक्रिया के दुष्चक्र में फंसने से बचे रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं। यही सहिष्णुता है जो हमें तनाव एवं क्रोध से बचाती है। दरसअल यह सहिष्णुता ही हमें एक 'परिपक्व' व्यक्ति बनाती है। इसी से इंसान अहं के शिकंजे से मुक्त हो सकता है। स्वयं को सह-अस्तित्व से जोड़ सकता है। बौद्धिक विनम्रता को जागृत कर सकता है। वैचारिक समन्वय स्थापित कर सकता है। सुख-दुख की संवेदना में संतुलन बना सकता है।

शांतिपूर्ण जीवन का मूलमंत्र है अहिंसा। हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होता है और शांति स्थापना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हिंसा विनाश का, कष्ट और विद्रोह का मार्ग है। हिंसा से दबाई गई समस्या अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और समय पाकर भयंकर विस्फोट के साथ भड़कती है। वस्तुतः सहिष्णुता बीज है और अहिंसा उत्पाद। सहिष्णुता अहिंसा का पर्याय ही तो है। असहिष्णुता अस्वीकृति को जन्म देती है और यह अस्वीकृति ही विभिन्न विवादों का कारण बनती है और परिणाम होता है हिंसा, तनाव, क्रोध। इंसान के चरित्र का भूगोल बिगड़ गया है। उसके दूषित विचारों और व्यवहारों ने जीवन को इतना प्रदूषित कर दिया है कि संस्कृतियां बिखरने लगी हैं, परंपराएं चरमरा रही हैं और आदर्शों के मानक बदलने लगे हैं। जरूरत सिर्फ सोच की दिशाओं को बदलने की एवं गलत धारणाओं का भार उतारने की है, अपनी जड़ता को समाप्त करने की है। इंसान ने अपने अस्तित्व की सुरक्षा में औरों का व्यक्तित्व बौना बना दिया है। इन जटिल स्थितियों में अहिंसा जीवन को शांतिपूर्वक जीने की वास्तविक सच्चाई है। अहिंसा सबका सहारा है। यदि हमें एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुखी एवं विकासमान संसार का निर्माण करना है तो अहिंसा भाव अर्थात सहिष्णुता को स्वीकारना और अपनाना होगा। **ललित गर्ग**

समझना होगा विविधता का महत्व

देवेंद्रराज सुथार

कई जीव और फसलें ऐसी हैं जिनकी मूल प्रजातियों का होना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने पेरिस में 'ग्लोबल असेसमेंट स्टडी' जारी करते हुए कहा कि प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र में विविधिता का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जलवायु परिवर्तन से मुकाबला। जिन वनस्पतियों और जीवों पर खतरा मंडरा रहा है उन पर रिपोर्ट कहती है कि मानवीय गतिविधियां पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रजातियों को जोखिम में डाल रही हैं। पौधों और जीव समूहों की करीब 25 फीसद प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। अगर जैव विविधता के गायब होने वाले कारकों से निपटने के लिए प्रयास नहीं हुए तो दस लाख से अधिक प्रजातियों के कुछ ही दशकों में विलुप्त हो जाने की आशंका है।

रिपोर्ट का कहना है कि मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद 2016 तक, पालतू स्तनधारी पशुओं की 6,190 में से 559 प्रजातियां विलुप्त हो गईं। उनका इस्तेमाल भोजन तैयार करने और कृषि उत्पादन में किया जाता था। एक हजार प्रजातियों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। कई फसलें ऐसी हैं जिनकी जंगली प्रजातियों का होना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन उन्हें प्रभावी संरक्षण नहीं मिल पा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर पहले की तुलना में कहीं अधिक भोजन, ऊर्जा और सामग्री को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रकृति की कीमत पर हो रहा है और भविष्य में यह योगदान जारी रखने की उसकी क्षमता प्रभावित हो रही है। वहीं प्रदूषण के मुद्दे पर मिश्रित वैश्विक रुझान देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वायु, जल और भूमि प्रदूषण का बढ़ना अब भी जारी है। समुद्री जल में प्लास्टिक प्रदूषण में 1980 के बाद से 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है जिससे कम से कम 267 प्रजातियों के लिए खतरा बढ़ गया है। इनमें 86 फीसद समुद्री कछुए, 44 फीसद समुद्री पक्षी और 43 प्रतिशत समुद्री स्तनपायी जीव हैं। अपनी तरह की यह पहली रिपोर्ट है जिसमें मूल निवासियों और स्थानीय लोगों के ज्ञान, मुद्दों और प्राथमिकताओं को भी शामिल किया गया है।

निरंतर तीव्र गति से हो रही वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट व खतरनाक रसायनों के समुद्र में मिलने व मानव द्वारा अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु किए गए जंगली जानवरों के शिकार जैसे मानवीय क्रियाकलाप प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार कारक है। जैव विविधता का ह्रास मानवीय अस्तित्व के अंत का सूचक है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने व मानव की उदरपूर्ति के लिए जैव विविधता एक अनिवार्य है। यदि जैव विविधता का इसी गति से ह्रास होता गया तो खाद्य श्रृंखला व जैविक चक्र का क्रम बिगड़ने के कारण मनुष्य का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जरूरत है कि हम आने वाले खतरे को भांपते हुए अभी से संजीदा होकर आवासीय उपलब्धता के लिए जंगलों का साफ कर रही बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करें, ऐसे उद्योग-धंधों को बंद करें जो वन्यजीवों को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मुद्दों से भटकती देश की राजनीति

प्रधान संपादक संजय गुप्त ने अपने आलेख 'सार्थक संवाद के बजाय वाद-विवाद' में कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाली निरर्थक तू-तू, मैं-मैं की जगह भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे पर सार्थक बहस की जो जरूरत बताई है, वह उचित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की राजनीति मुख्य मुद्दों से भटक कर, अमर्यादित भाषा से युक्त आरोप-प्रत्यारोप से आम जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। चुनाव के माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का एक दूसरे के लिए स्तरहीन भाषा में बयानबाजी करना, लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। देश के प्रधानमंत्री को बिना किसी सबूत के 'चोर' बताना बदस्तूर जारी है। सिद्धांततः आम चुनाव की चर्चा के बीच पक्ष-विपक्ष में राष्ट्रीय मुद्दों पर तार्किक और सार्थक संवाद होना चाहिए, न कि अमर्यादित शब्दों में एक दूसरे के व्यक्तित्व को लांछित करने वाली अनावश्यक टिप्पणियां। लेकिन न जाने क्यों इस बार पूरा विपक्ष बहुत ही भदेस भाषा में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को निशाना बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के अनादर की यह पराकाष्ठा है। इस पर जब सहनशीलता की सीमा समाप्त होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार की दुखती रग पर हाथ रख दिया तो मर्यादा की दुहाई दी जाने लगी। लोकतांत्रिक स्वस्थ राजनीति के लिए आपसी आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए, उन मुद्दों पर सार्थक बहस होनी चाहिए जिनसे आम जनता का सीधा सरोकार है। इसके लिए चुनाव आयोग को भी कड़े नियम निर्धारित कर नेताओं की बदजुबानी पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

आत्ममंथन करे पत्रिका और लेखक

टाइम पत्रिका ने हालिया संस्करण में इंडियाज डिवाइडर इन चीफ शीर्षक से एक आवरण कथा छापी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का विभाजक बताया गया है। टाइम का यह शीर्षक विवादों में घिर गया है। भाजपा जहां इसे सिरे से खारिज कर रही है वहीं अन्य दल इसे आड़े हाथों लेकर मोदी की असलियत बता रहे हैं। मगर क्या यह तथ्यात्मक रूप से सही है? इस लेख को लिखने वाले पाकिस्तानी नेता सलमान ताशीर के पुत्र आतिश ताशीर हैं। उन्होंने यह किस आधार पर कहा है? क्या मोदी ने सरकारी योजनाओं का वितरण जातिगत आधार पर किया है या फिर आए दिन सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं? क्या एक विशेष समुदाय देश छोड़कर पलायन कर रहा है या फिर मस्जिद और चर्चों में गोलियां चल रही हैं? अगर नहीं तो यह लेख किस विभाजन की बात कर रहा है? रही बात कथित गोरक्षकों की तो सनद रहे प्रधानमंत्री ने अपने मंच से ऐसे फर्जी लोगों को कड़ी हिदायत देते हुए चेताया है। किसी भी ऐसी घटना को कानून की विफलता के अलावा मजहब के चश्मे से क्यों देखा जाता है? अब सवाल यह है कि क्या ऐसी मशहूर पत्रिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 5 सालों को एक विवादित शीर्षक में कैद करना चाहिए जिसका कोई मजबूत आधार न हो? इस शीर्षक को गलत साबित करने वाले आधार हैं, जिसमें हाल ही में दो बड़े राष्ट्रों रूस और यूएई द्वारा मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही कुछ माह पूर्व ही दक्षिण कोरिया ने सियॉल पीस प्राइज तथा संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ मोदी को दिया है। तो क्या शांति पुरस्कार अशांति और सर्वोच्च सम्मान बंटवारे के लिए मिलता है? पत्रिका के इस लेखक को इन तर्कों पर जवाब देना चाहिए और शायद आत्मचिंतन भी करना चाहिए।

संजय दुबे, नई दिल्ली

बेटियों के प्रति सोच

आधुनिक समाज में भी लड़कियों को पूरी आजादी नहीं मिल सकी है। वह न अपनी पसंद से व्यवसाय चुन सकती है और न ही अपनी पसंद से शादी कर सकती है। हालांकि कुछ परिवारों में इसकी आजादी है, लेकिन ज्यादातर परिवारों में लड़कियों के मामले में परिजन ही फैसला लेते हैं। जबकि लड़कों के मामलों में ऐसा नहीं है। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चला रही है, वहीं बेटियों को फैसला लेने तक का अधिकार नहीं है। बेटियों के बारे में समाज को धारणा बदलनी होगी। हर घर परिवार में बेटियों से भी पूछा जाना चाहिए कि वह क्या पढ़ना चाहती है, कौन सी नौकरी या व्यवसाय करना चाहती है। उसकी मर्जी का सम्मान परिजनों को भी करना चाहिए। जिस दिन बेटियों के फैसले को महत्व मिलने लगेगा, उसी दिन से भारतीय समाज में बदलाव दिखेगा।

कोमल, सदर बाजार, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।